

मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० बिहार, पटना।

पत्रांक— बी०एस०बी०सी०सी०एल०— 020—2017(दक्षिण)

दिनांक:

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पटना ।

सेवा में,

सभी उप—महाप्रबंधक,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पटना ।

विषय:— वगैर स्वामित्व, अनापत्ति प्रमाण—पत्र तथा फॉर्म 'एम' व 'एन' के सत्यापन के कराये गये कार्य
के विपत्र भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंग:— खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक 1571 दिनांक 15.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि जिन
निर्माण/मरम्मत/जिर्णोद्धार कार्यों में Royalty आधारित सामग्रियों का व्यवहार किया जाता है, वैसे कार्यों के
विपत्र का भुगतान स्वामित्व, अनापत्ति प्रमाण—पत्र तथा फॉर्म 'एम' व 'एन' के सत्यापन के उपरान्त ही करें, ताकि
राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

—

मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक:

दिनांक

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक (दक्षिण)/ महाप्रबंधक (उत्तर)/महाप्रबंधक(वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

—

मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक: 1842(अ५०)

दिनांक 22-6-17

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।

—

मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक-प्र0-01-मु0स्था-12/16-.....1571...../एम0,पटना, दिनांक- 15/6/17
प्रेषक,

Email / Fax/
Registered

सतीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर सचिव-सह-निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग/
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना।

महाप्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03,
प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्रीकृष्णापुरी,
बोरिंग रोड, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम,
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम,
निर्माण निगम, बी0एम0पी0-5 कैम्पस, शेखपुरा, पटना-14।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि0,
द्वितीय तल्ला, विद्युत भवन, बेली रोड बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नॉर्थ बिहार पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि0,
विद्युत भवन, बेली रोड बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक,
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि0,
भेटनरी कॉलेज कैम्पस, रिडिंग रोड, पेसू, एरिया, शेखपुरा, पटना।

प्रबंध निदेशक,
साउथ बिहार पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि0,
विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

AM(N) / AM(S)
Ampt/rai-

13
19-0-6-17

प्रबंध निदेशक कोषांग
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0
पत्र संख्या.....57/.....
दिनांक.....17/06/17

मुख्य महाप्रबंधक कोषांग
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0
पत्र संख्या.....57/.....
दिनांक.....17/06/17

प्रबंध निदेशक
बिहार ग्रीड कॉरपोरेशन लि०,
विद्युत भवन, बेली रोड बिहार पटना।

विषय:- बिना स्वामिस्व, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा फॉर्म 'एम' व 'एन' के सत्यापन के कराये गये कार्य की विपत्र भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(8), 40(9) एवं 40(10) के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई किये जाने संबंधी प्रावधान निम्नवत् उद्धृत किये जाते हैं:-

(x) **Rule 40(8)** - "Whoever removes minor mineral without valid lease / permit or on whose behalf such removal is made otherwise than in accordance with these Rules he be an agent, Manager, Contractor or a sub-lessee, shall be presumed to be a party to the illegal removal of the minor mineral and shall be liable to pay (the price thereof and the Government may also recover from such person rent, royalty or taxes as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority) without prejudice to other action being taken against him under these Rules or any other law for the time being in Force.

(xi) **Rule 40(9)**- Notwithstanding anything contained in rule 40(8) hereinbefore whosoever, under the terms of an agreement other than an agreement under these rules at any time has received or receives cost of minor mineral/ material including royalty under the terms of the said agreement shall deposit that royalty which is included in such cost of mineral / material in the manner prescribed in rule 43 hereinafter, within seven days from the date of receipt of such cost of mineral / material.

Any royalty received as such by such person before the commencement of this rule shall be deposited by him within fifteen days from the date of commencement of this rule.

Provided that if a sum equal to the royalty included in the cost of mineral / material so received has already been paid or deposited prior to receipt of cost of the mineral / material including royalty by him he shall not be required to deposit the royalty said above.

Provided further that any royalty payable under this rule, if not paid when due be recovered with interest @ 15 percent per annum as an arrear sum of public demand."

(xii) **Rule 40(10)**- "To prevent evasion of royalty it is provided that works contractor shall purchase the minerals from lessee/permit holder and authorized dealers only and no Works Department shall receive the bill which the works contractors submit to recover cost etc. of mineral used by them in completion of the works of the Works Department under any agreement from the works contractor if the said bill is not accompanied by an affidavit in Form "M" with particulars in Form "N" of these rules along with a photo copy of the said affidavit and particulars. It shall be the duty of the officer who receives or on whose behalf the said bill is received to send the photocopy of the Affidavit and particulars to the District Mining Officer/Assistant Mining Officer within whose jurisdiction the mineral was allegedly purchased, for verification.

If contents of the said affidavit on verification by the concerned District Mining Officer/Assistant Mining Officer is found to be false either wholly or partly is shall be presumed that the concerned minerals was obtained by illegal mining and in that event the said District Mining Officer/Assistant Mining Officer shall take action as prescribed in these rules against the maker of the said affidavit.

Provided that if the works contractor deposits or pays the royalty in respect of the mineral so consumed /supplied by him as shown in the aforesaid affidavit and particulars the said District Mining Officer/Assistant Mining Officer in his discretion may not take action as prescribed in this rule."

Explanation – For the purposes of this rule:-

(iv) "Works Department" means department of the Central or State Government including Company, Corporation, Undertakings, Autonomous body of the government engaging works contractors for any kind of construction on its behalf.

"Works Contractor" means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals who under an agreement, with the Works Department work for the said Department."

अतएव उपर्युक्त नियमों के आलोक में अनुरोध है कि बिना स्वामिस्व, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा फॉर्म 'एम' व 'एन' के सत्यापन के कराये गये कार्य के विपत्र भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाने की कृपा की जाय, जिससे कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

विश्वासभाजन

अपर सचिव-सह-निदेशक